



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2013/श्रावण 21, 1935

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2013/SRAVANA 21, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सर्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013

सं. 22 (आर.ई. 2013)/2009-2014

विषय : निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने का विकल्प ।

फा. सं. 01/94/180/395/एएम 13/पीसी 4.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा (क) शुल्क छूट स्कीम (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 4.28) और (ख) ईपीसीजी स्कीम (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 संशोधित संस्करण 2012 का पैरा 5.14) के तहत निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं ।

(क) निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार धारक द्वारा लागू सीमा-शुल्क का भुगतान कर नियमित किया जा सकता है, जो निर्यात दायित्व में कभी के अनुरूप हो और साथ में ऐसे सीमा-शुल्क पर ब्याज भी देय होगा, लेकिन इस प्रकार देय ब्याज इस चूक के लिए देय सीमा-शुल्क की राशि से अधिक नहीं होगा ।

[एक उदाहरण यहां दिया जाता है : माना कि निर्यात दायित्व में चूक 100% है, इसका अर्थ होगा कि बचाए गए पूरे शुल्क की राशि वापस (रिफंड) करनी होगी । इस बचाए गए शुल्क की राशि पर ब्याज की गणना आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक करनी होगी । इस छूट के तहत ब्याज की राशि, बचाए गए शुल्क की मात्रा तक सीमित होगी । यदि बचाए गए शुल्क की मात्रा 150 रुपये थी, तो ब्याज भी 150 रुपये तक सीमित होगा और इस कारण इस मामले के नियमितीकरण के लिए प्राधिकार धारक द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि 300 रुपये होगी । तथापि उतनी ही बचाई गई 150 रुपये की शुल्क राशि के लिए, यदि निर्यात दायित्व 30% था तो बचाई गई संगत शुल्क राशि 45 रुपये हो जाती है (150 रुपये का 30%) । इस प्रकार ब्याज 45 रुपये तक सीमित होगा । अतः 150 रुपये की बचाई गई शुल्क राशि के लिए निर्यात दायित्व में 30 प्रतिशत चूक के इस नियमितीकरण के लिए शुल्क+ब्याज 90 रुपये से अधिक नहीं होगा ।]

(ख) मौजूदा नीति के अनुरूप सीमा-शुल्क का भुगतान या तो नगद या विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किसी भी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को नामे डालकर (डेबिट करके) किया जा सकता है । लेकिन, ब्याज की राशि का भुगतान केवल नकद ही करना होगा ।

(ग) यह लाभ उठाने का निर्णय लेने वाले किसी भी प्राधिकार धारक को इस भुगतान की प्रक्रिया 31 मार्च, 2014 तक अथवा उससे पहले पूरी करनी जरूरी है।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट दायर करने की प्रणाली सहित, आवश्यक प्रक्रियाएं अलग से स्पष्ट की जाएंगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : निर्यात दायित्व में चूक के पुराने मामलों के मोचन/नियमितीकरण हेतु एक विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th August, 2013

No. 22 (RE-2013)/2009-2014

Subject : Option to close cases of default in Export Obligation.

F. No. 01/94/180/395/AM 13/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby provides a procedure to close cases of default in Export Obligation under (a) Duty Exemption Scheme (para 4.28 of the HBP v1 and (b) EPCG Scheme (para 5.14 of HBP v1 RE-2012).

(a) All pending cases of the default in meeting Export Obligation (EO) can be regularised by the authorisation holder on payment of applicable customs duty, corresponding to the shortfall in export obligation, along with interest on such customs duty; but the interest component to be so paid shall not exceed the amount of customs duty payable for this default.

[Here is an example : Suppose the default in EO is 100%, this would mean the complete duty saved amount has to be refunded. The interest on this duty saved amount has to be calculated from the date of import till the date of payment. The interest component under this dispensation would be limited to the duty saved amount. If the duty saved amount were Rs. 150, then the interest component would be limited to Rs. 150 and therefore for regularising this case the maximum amount to be paid by the authorisation holder would be Rs. 300. However, for the same duty saved amount of Rs. 150, if the default in EO were 30%, then the corresponding duty saved amount becomes Rs. 45 (30% of Rs. 150). Hence the interest component will be limited to Rs. 45. Thus, duty + interest will not exceed Rs. 90 for this regularisation of 30% default in EO for a duty saved amount of Rs. 150.]

(b) In line with the existing policy the customs duty could be paid either in cash or by way of debiting of any valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy. The interest component however, has to be paid in cash only.

(c) Any authorisation holder choosing to avail this benefit must complete the process of payment on or before 31st March, 2014.

(d) Necessary procedures including a system of filing required reports by the respective RAs would be indicated separately.

Effect of this Public Notice : An option is being provided for redemption/regularisation of old cases of EO default.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade